

कृषि ऋण की माफी से मुद्रास्फीति में वृद्धि संभव

चर्चा में क्यों?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का मानना है कि कृषि ऋण की माफी से मुद्रास्फीति स्थायी रूप से 0.2 प्रतिशत बढ़ेगी। आरबीआई के एक दस्तावेज़ में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2017-18 में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सात राज्यों में 88,000 करोड़ रुपए की कृषि ऋण माफी को लागू किया जाना है और इससे मुद्रास्फीति में इज़ाफा होगा।
- दरअसल, देश में केंद्र और राज्य सरकारों दोनों द्वारा कृषि ऋण को माफ करने की घोषणा की जाती है और इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा-फसल नुकसान से संकट झेल रहे किसानों को राहत प्रदान करना होता है। आरबीआई की ओर से जारी एक दस्तावेज़ में कहा गया है कि ऋण माफी से मध्यम अवधि में राजकोषीय बोझ बढ़ेगा।

कृषि ऋण माफी की चित्तौं

- किसानों की आय बढ़ाने के लिये समन्वय और नरितर परयासों का अभाव है और किसान जब भी वरिध दरज़ कराता है तो करज़ माफी को त्वरति उपाय के रूप में अमल में लाया जाता है।
- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों ने चालू वतित वर्ष में 1.3 ट्रिलियन रुपए के करज़ माफी को मंजूरी दी है जो कि जीडीपी के 0.8% के बराबर है। ऋण माफी के कारण ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच बनाना मुश्किल हो जाता है।
- महाराष्ट्र सरकार ने जहाँ सभी किसानों की ऋण माफी की योजना बनाई है, वहीं उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों को यह छूट दी गई है। इन परस्थितियों में यह चुनाव करना कठिन हो जाता है कि कौन ज़्यादा ज़रूरतमंद है, क्योंकि सभी ऋण माफी के लिये परयास कर रहे होते हैं।
- ऐसे किसान जो ऋण चुकाने का खर्च वहन कर सकते हैं, ऋण माफी की उम्मीद में वे भी अपना ऋण नहीं चुकाते हैं। इससे होता यह है कि भवषिय में बैंक किसानों को उधार देने के लिये अनचिछुक हो जाते हैं।
- साथ ही ऋण माफी सरकार की वतिततीय प्रणाली को अव्यवस्थति कर देती है। दरअसल, ऋण माफी भी चुनावी जीत के लिये एक रणनीति बन गई है, जिसमें राजनीतिक दलों और बड़े किसानों को फायदा होता है जबकि छोटे और सीमांत किसानों के हालात स्थिर रहते हैं। इसके अलावा, चयनात्मक ऋण माफी को भी ठीक ढंग से परिभाषति नहीं किया गया है।

क्या होना चाहिये?

- इसमें कोई शक नहीं है कि ऋण माफी से किसानों को काफी राहत मिली है, लेकिन इस तरह की माफी का कोई दीर्घकालिक प्रभाव अभी तक देखने को नहीं मिला है।
- हालाँकि करज़ माफी से किसानों को अस्थायी राहत मिल सकती है, फरि भी कृषि को स्थायी बनाने के लिये एक दीर्घकालिक प्रभावी उपाय की आवश्यकता है। दीर्घकालिक उपायों में शामिल हैं:

- तकनीक उन्नयन से अक्षमता में कमी लाना।
- कृषि लागत में कमी लाना।
- किसानों की आय में वृद्धिका परयास करना।
- बीमा योजनाओं के माध्यम से फसल सुरक्षा सुनिश्चति करना।
- सचिाई क्षमता को बढ़ाना।
- कोल्ड स्टोरेज चैन का निर्माण करना।
- कृषि क्षेत्र को सीधे बाज़ार से जोड़ना।